तपती धरती

पर्यावरण संरक्षण में प्राकृतिक खेती की महत्ता

तपती धरती का प्रकाशन पर्यावरण संरक्षण, मौसम चक्र परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से उठते विश्वव्यापी खतरे जैसे विषयों पर जनजाग्रति के उद्देश्य से किया गया है। इसके माध्यम से हम जल, जंगल, जमीन, हवा, वनस्पति, वन्य प्राणी, जीव-जंतु आदि सभी के जीवनकाल पर पड़ने वाले खतरे को लेकर उसके संरक्षण की दिशा में मानव पहल पर केन्द्रित सामग्रियों का प्रकाशन करते आए है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई एक ऐसा घटक नहीं है जिसके लिए कार्य करने पर इसे सुरक्षित रखते हुए हम संभावित खतरे से बच सके। बल्कि इस संबंध में चौतरफा कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे दैनिक जीवनकाल में ऐसे अनेक कार्य है जिससे हम कहीं न कहीं अपनी सेहत के साथ ही प्रकृति से भी खिलवाड़ करते रहे है, बल्कि कर भी रहे है। इससे केवल शासकीय स्तर पर चलाई जाने वाली कागजी योजनाओं भर से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए मानव समाज को ही सामूहिक पहल करना होगी। लेकिन किसी भी अच्छे कार्य की पहल के लिए चिंतन मंथन तो बहुत से लोग करते है, किंतु आगे आने के लिए समय किसी के पास नहीं होता। जिन संस्थाओं द्वारा इस दिशा में पहल की जाती है हम अक्सर उसके कार्य में भी किंतु परंतु और उसके हितलाभ को देखने लगते है। जबकि वास्तव में जमीनी स्तर पर किए जाने वाले ऐसे छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ा जनआंदोलन बनकर परिवर्तन का कारक बनता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है। चूंकि वर्तमान कृषि पद्धति न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रही है बल्कि वह सृष्टि में विद्यमान जीव मात्र के लिए घातक साबित हो रही है। मानव स्वास्थ्य पर तो इसका विपरीत असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है लेकिन जीव-जंतु, जल और जंगल पर भी इसके दुष्प्रभाव से अब दुनिया वाकिफ होने लगी है। हम इस बार के अंक में प्राकृतिक कृषि से उत्पादित मोटे अनाज और उसकी महत्ता तथा इस दिशा में किए जाने वाले सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश डाल रहे है। यह अंक हरदा जिले में रुपई वनश्री के बैनर तले प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के कार्यों तथा उत्पादित मोटे अनाज के लिए जनजागृति की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को विशेष रुप से रेखांकित कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे द्वारा तपती धरती के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाने वाली पठनीय सामग्रियों में पूर्व की भांति यह पहल भी पसंद आएगी। इस दिशा में आपके सुझाव, आपके विचार लेख के रुप में भी हम सादर आमंत्रित करते है। आपके द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी किसी भी पहलू को लेकर लिखे जाने वाले लेख समाज में जनजागृति का कार्य करेंगे।

मोटा अनाज खाओं और पतले हो जाओं

"हम जंगल से चले थे, लेकिन स्वस्थ्य थे। जब जंगलों से बाहर निकले तो हमने उस प्रकृति से ही खिलवाड़ करना शुरु कर दिया जिसकी गोद में खेल कर हम अपने अस्तित्व को पहचान पाए थे। भौतिकता की अंधी दौड़ में हमने न केवल स्वयं को प्रकृति से दूर किया है बल्कि उसके दोहन के बजाए उसका शोषण करना शुरु कर दिया। हम पहले अशिक्षित थे, लेकिन सुरक्षित थे। हमने शिक्षा का उपयोग बेशक चांद पर पहुंचने तक किया हो लेकिन हमारी इन्हीं उपलब्धियों ने हमें अपनी जड़ से दूर कर दिया। प्रकृति का मूल सिद्धांत है कि जिस वृक्ष की जड़े जमीन छोड़ देती है वह ज्यादा समय खड़ा नहीं रह सकता। आज हमारी स्थिति ऐसे ही वृक्ष के समान नजर आने लगी है। हम प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते करते उसका दुरुपयोग कर दुनिया का चक्कर लगा आए लेकिन आखिर हमें आज उसी प्रकृति के पास पहुंचने के लिए विवश होना पड़ रहा है जहां से हम चले थे।"

आज हमारे पोषक तत्वों में कमी ही एक गंभीर समस्या बनते जा रही है। व्यस्ततम जिंदगी के चलते हम प्रोस्टेड फूड, फास्ट फूड और डिब्बा बंद फूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके है जो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहे है। आज उत्पादित किए जाने वाले अनाज और सब्जियों में भी रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के चलते हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स आदि की मात्रा में 20 प्रतिशत तक की कमी आंकी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। जिसके चलते अब हम वापस उसी प्रकृति प्रदत्त मोटे अनाज की ओर लौट रहे है जो कभी हमारी थाली का मुख्य हिस्सा हुआ करता था।

- **वनांचल से लगे गांवों में उत्पादित किया जाएगा प्राकृतिक रुप से मोटा अनाज।**
- **कृषक समूह बनाकर प्राकृतिक कृषि को दिया जाएगा बढ़ावा।**
- **महिला समूह के माध्यम से होगी कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग।**
- **परंपरागत पद्धति से ग्रामीण महिलाएं ही तैयार करेगी दालें।**
- **कोदा कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग के उत्पाद पर दिया जाएगा जोर।**
- **वनवासियों को अपना कृषि उत्पाद बेचने नहीं जाना पड़ेगा मंडी।**
- **वनांचलों में फड़ लगाकर खरीदी करने वाले बिचौलियों से मिलेगी निजात।**
- **फसलों के मूल्य पश्चात उसकी बिक्री के लाभांश का भी मिलेगा किसानों को लाभ।**

हाल ही में दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन में आए दुनिया भर के मेहमानों ने मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों को भरपूर सराहा है। अब देश और विदेश की सरकारें इसी मोटे अनाज को महत्व देने लगी है।

इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हरदा जिले के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष पर्यावरणविद् गौरीशंकर मुकाती अपनी टीम के माध्यम से रुपई वनश्री के बैनर तले वनांचल के किसानों को प्रोत्साहित कर प्राकृतिक खेती अपनाने और मोटा अनाज उत्पादित करने की पहल कर रहे है। आज अधिकांश लोग अपनी सेहत को लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे है। कोई योगासन, प्राणायाम, नेचरोपैथी सेंटर, आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा आदि लेते हुए अपना मोटापा और वजन कम करने की कवायद कर रहा है। लेकिन मोटा अनाज एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके खाने से मोटापा भी कम होता है और वजन भी तेजी से घटता है। तो आईए मोटा अनाज खाएं और पतले हो जाएं।

धरती को बचाने और पीढ़ी संवारने का काम करती है प्राकृतिक खेती

“ रासायनिक खाद एवं कीटनाशक प्रभावित खान-पान से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पहले जितनी ही पैदावार लेने के लिए इस खेती में लगातार पहले से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसलिए आज नहीं तो कल, रासायनिक खादों, यूरिया इत्यादि के बिना खेती करनी ही पड़ेगी। एक और बात पाई गई है, प्राकृतिक खेती अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहले रासायनिक खेती भी जोर-शोर से अपनाई थी और अनेक पुरस्कार प्राप्त किये परन्तु जब कुछ समय बाद उससे बहुत नुकसान होने लगा तब उन्होंने नये रास्ते तलाशने शुरू किये और अंततः प्राकृतिक आधारित खेती पर पहुंचे। ”

प्राकृतिक खेती मानव ही नहीं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए भी जरुरी है। इससे जहां मिट्‌टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली होती है तो वहीं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन भी होता है। कम लागत और कर्जविहीन खेती का यह एक सर्वोत्तम पुरातन माध्यम है। जिसे हमने और अधिक की चाहत में तिलांजलि देते हुए अत्याधुनिक खेती तकनीक को अपनाकर प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ करने का कार्य किया है। वैसे तो देश के अनेक प्रांतों में अब किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया जा रहा है। चूंकि रासायनिक खाद-बीजों के माध्यम से हमने अधिक उत्पादन की चाह में भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती अपनाने पर शुरुआती वर्षों में कम उत्पादन होने के कारण किसान इसे आसानी से नहीं अपना पाते है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को न्यूनतम औसत उत्पादन के मान से अंतर राशि प्रदान कर प्रोत्साहित करने का कार्य भी कुछ स्थानों पर कर रही है। हाल ही में मध्यप्रदेश के हरदा जिले के वनांचल में रुपई एग्री फॉरेस्ट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा छोटी जोत वाले वनवासी किसानों को प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों को अच्छे दामों पर क्रय करते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। यह पहला वर्ष है जब यहां के किसानों को विशुद्ध रुप से प्राकृतिक उत्पादों को बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों पर न बेचने तथा मंडियों में रासायनिक उत्पाद के समानांतर भाव से निजात दिलाते हुए उन्हें अच्छे दाम देने की कवायद की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लम्बे समय से वृक्षारोपण के माध्यम से वसुंधरा

हरदा जिले के वनांचल में प्राकृतिक खेती बनेगी लाभ का धंधा

का श्रृंगार करने में जुटे हरदा जिले के पर्यावरणविद् गौरीशंकर मुकाती का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में चौतरफा कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारी लाईफ स्टाईल और व्यवसाय को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ठीक उसी विचारधारा को श्री मुकाती अपनी कंपनी रुपई एग्री फॉरेस्ट के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे है। उनका मानना है कि आज के वर्तमान परिवेश में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कृषि के क्षेत्र में अधांधुंध रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। फलतः आम जनता के साथ-साथ किसानों को भी कई दुष्परिणाम भुगतनें पड़ रहे हैं। इससे किसान का खर्च और कर्ज बढ़ रहा है और बावजूद इसके आमदनी का कोई भरोसा नहीं है। रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं हाइब्रीड बीज अत्यधिक मंहगे दर पर मिलते है। बैंक ऋण के जाल में पड़ने की वजह से किसानों के आत्महत्या मामलों में वृद्धि हुई है।

रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम और प्रदूषित हो रहा है तथा हानिकारक कीटों की वृद्धि हो रही है। कंपनी पर रासायनिक उर्वरक, संकर बीज कीटनाशक के लिए निर्भरशीलता बढ़ रही है। मिट्टी, पानी एवं हवा से विभिन्न प्रकार के लाभकारी जीव जैसे- मछ्ली, केचुआँ एवं अन्य कीट पतंगों की कमी हो रही है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक प्रभावित खान-पान से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पहले जितनी ही पैदावार लेने के लिए इस खेती में लगातार पहले से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसलिए आज नहीं तो कल, रासायनिक खादों, यूरिया इत्यादि के बिना खेती करनी ही पड़ेगी। एक और बात पाई गई है, प्राकृतिक खेती अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहले रासायनिक खेती भी जोर-शोर से अपनाई थी और अनेक पुरस्कार प्राप्त किये परन्तु जब कुछ समय बाद उससे बहुत नुकसान होने लगा तब उन्होंने नये रास्ते तलाशने शुरू किये और अंततः प्राकृतिक आधारित खेती पर पहुंचे।

अब वनवासी करेंगे प्राकृतिक उत्पाद को परंपरागत तरीके से तैयार

हरदा जिले के वनांचल और उससे जुड़े ग्रामीण अंचलों में छोटी जोत वाले किसानों को अक्सर अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए परेशान होना पड़ता है। चूंकि कम खेती होने के कारण उनका उत्पादन कम होता है ऐसी स्थिति में किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी ले जाना परिवहन लागत से महंगा पड़ता है। स्वयं के परिवहन संसाधन न होने के कारण अक्सर दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। वहीं आर्थिक तंगी भी ऐसे किसानों के लिए एक अहम कारक होती है। जिसके चलते वह अपने क्विंटल चार क्विंटल अनाज को लेकर मंडी आने के बजाए क्षेत्र में ही फड़ी लगाकर अनाज खरीदने वाले बिचौलिए व्यापरियों को औने-पौने दामों पर बेच देता है। उसे नहीं पता कि उसके द्वारा उत्पादित यह प्राकृतिक उत्पाद वास्तव में सेहत की दृष्टि से कितना गुणकारक है और इसकी बाजार में कितनी मांग है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिले के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष तथा पर्यावरण के क्षेत्र में लम्बे अरसे से कार्य करने वाले गौरीशंकर मुकाती ने एक वृहद कार्ययोजना बनाई है। जिसके तहत जिले के ऐसे उपरोक्त किसानों से सीधे संपर्क स्थापित कर उनका एक समूह बनाया जा रहा है। उन्हें प्राकृतिक खेती के माध्यम से ज्वार, बाजरा, कोदा, कुटकी, मक्का, अरहर, मूंग आदि उत्पादित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि जो भी किसान उपरोक्त उत्पाद प्राकृतिक रुप से उत्पादित करेगा उसे बाजार मूल्य से अच्छे दाम प्रदाय किए जाएंगे।

रुपई वनश्री के बैनर तले वनांचल के प्राकृतिक कृषि उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचाने और उनके उचित दाम दिलाकर उनका जीवन स्तर उठाने में कारगर सिद्ध होगी आदान-प्रदान योजना

ऐसे किसानों के समूह से लिखित अनुबंध किया जा रहा है कि उनके उत्पाद रुपई एग्री फॉरेस्ट कंपनी द्वारा क्रय किए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि वनांचलों में केवल मौसमी फसल लेने के बाद यहां के वनवासी रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्र में पलायन कर जाते है उन्हें अपने ही क्षेत्र में अपने ही द्वारा उत्पादित इस अनाज को परंपरागत रुप से बाजार हेतु तैयार करने का कार्य भी सौपा जाएगा। अरहर से दाल बनाने का कार्य वनवासी महिलाओं को समूह बनाकर दिया जाएगा। वहीं अन्य अनाजों की सफाई, बिनाई, अलग-अलग वजन आकार में पैकिंग जैसे कार्य भी इसी क्षेत्र के लोगों से कराए जाएंगे। जिससे इन्हें स्थानीय स्तर से रोजगार उपलब्ध हो सके। वहीं इनसे क्रय किए गए अनाज के लिए बाजार तलाश कर उसे बिक्री करने उपरांत प्राप्त होने वाले लाभांश का एक सुनिश्चित हिस्सा भी इन्हीं लोगों को कृषि प्रोत्साहन के रुप में प्रदाय किए जाने की योजना बनाई गई है।

दुनिया लौट रही मोटे अनाज की ओर

हमारे गांव में जो अनाज पहले हर घरों की थाली में आम हुआ करता था वह धीरे-धीरे आधुनिकता की भेंट चढ़ता गया। नई पीढ़ी शहर की सड़कों पर जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई उन्हें गांव से जुड़ी चीजें तुच्छ और पिछड़ेपन की निशानी लगने लगी। ज्वार, बाजरा, कोदा कुटकी जैसे पारंपरिक अनाजों को वह जानवरों का चारा बताने लगे। भौतिक विकास की चकाचौंध में हमने इस परंपरागत अनाज से दूरी बनाना शुरु कर दिया। जिसके चलते इसकी मांग में कमी आने के कारण किसानों ने भी आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर भरपूर उत्पादन प्राप्त करने की चाह में उस परंपरागत कृषि को छोड़ दिया। जो किसान छोटे जोत के खेत में एक या दो फसल लेकर भी बिना बैंक कर्ज के अपना गुजर बसर आसानी से कर लेता था उसे भी बाजार में बिकने वाले अनाज को महत्व देना पड़ा। परिणाम यह रहा कि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ती गई और उसी के साथ मिट्टी और मानव दोनों की सेहत खराब होती चली गई।

आज हम जिन उत्पादों को अपना मुख्य आहार बनाए हुए है उससे हम पोषक तत्वों की कमी के साथ ही तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में निरंतर कमी देख रहे है। बेशक आधुनिक खेती से किसानों की माली हालत में सुधार आया हो लेकिन अब वही किसान पुनः कर्ज के बोझ तले दबते हुए खेती को घाटे का सौदा मानकर शहरों की ओर पलायन करने लगा है। जबकि परंपरागत प्राकृतिक खेती अपनाने के दौरान हमारी ग्रामीण आबादी आर्थिक मानकों पर भले ही पिछड़ी थी, लेकिन सेहत के मानकों पर शहरी आबादी से कई गुना बेहतर थी। आज किसानों की जेब खाली है और सेहत खराब है।

अब देश दुनिया के लोग वैज्ञानिकों के रिसर्च पश्चात फिर घूमकर वहीं पहुंच रहे है जहां वर्षों पहले हमारे ग्रामीण कृषक जिस सेहतवर्धक मोटे अनाज का सेवन करते थे। जिस प्राकृतिक खेती को अपनाकर वह स्वस्थ्य और तंदरुस्त रहता था उसी दिशा में आज फिर सरकारों को भारी भरकम बजट के साथ कृषि को दिशा देने का कार्य करना पड़ रहा है। जिस कोदा-कुटकी, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे अनाजों को हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपना मुख्य दैनिक आहार बनाए हुई थी आज उसे ही महानगरों की फाईव स्टार होटलों में मुख्य और स्पेशल डिस के रुप में परोसा जाने लगा है। अब कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग से उत्पादित की जाने वाली फसलों से तौबा करते हुए शहरी धनपति भी मोटे दाम पर प्राकृतिक कृषि उत्पाद खरीदने को ललायित होने लगे है। कहने का आशय यह है कि देश और दुनिया का रुख अब मोटे अनाज की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है।

मेरी सेहत मेरे हाथ

प्रकृति की गोद से लें सेहत का खजाना

हरदा। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सेहत की सुरक्षा को लेकर हरदा जिले में एक नई पहल की जा रही है। रुपई एग्री फारेस्ट द्वारा अब रुपई वनश्री के माध्यम से वनांचलों में पैदा किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक वृहद कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत पिछले दिनों एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। पर्यावरण प्रेमी गौरीशंकर मुकाती की पहल पर आईए एक समावेशी समाज का निर्माण करें विषय पर हरदा में गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें शहर के प्रबुद्ध वर्ग को आमंत्रित किया गया था।

इस परिचर्चा में वनांचलों में उत्पादित होने वाले प्राकृतिक खेती के माध्यम से मोटे अनाज के उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान रुपई वनश्री के माध्यम से एक कार्ययोजना बनाकर कार्य करने वाले गौरीशंकर मुकाती ने कहा कि हमारी वनभूमि में कार्बोहाईड्रेड की मात्रा कम है और फायबर अधिक उत्पादन करने की अद्भुत प्राकृतिक क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे वनांचल और उससे जुड़े क्षेत्रों में ज्वार, मक्का, कोदो कुटकी, अरहर, मूंग जैसे बहुमूल्य मोटे अनाज परंपरागत प्राकृतिक कृषि के माध्यम से ही उत्पादित किए जाते है। यह अनाज सहजता से पकने और पचने वाले होते है। प्रकृति की गोद में पल्लवित होने वाले इस सेहत के अनमोल खजाने का हम उपयोग नहीं कर पाते है। चूंकि यहां की भूमि हल्की होती है और इसमें सामान्य क्षेत्रों की तुलना उतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। हमारी समाज और सरकार दोनों ने ही इन क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले अनाजों की महत्ता और गुणवत्ता को कभी सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा है। जिसके कारण इस क्षेत्र के किसान सामान्य क्षेत्र के किसानों की देखादेखी अपनी परंपरागत कृषि को छोड़कर गेहूं, चने जैसी खेती को अपनाने लगे। जिसके दुष्परिणाम यह रहे कि उन्होंने पहाड़ी नदी-नालों के पानी का उपयोग इस खेती के लिए करना शुरु कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में पैदा होने वाले मोटे अनाज की खरीदी के लिए भी सरकारी स्तर पर कोई विस्तृत कार्ययोजना नहीं बन पाई जिसका फायदा इस क्षेत्र में फड़ी लगाकर खरीदी करने वाले बिचौलियों द्वारा उठाया जाने लगा। आज हम इन्हीं सब विषयों को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण और समाज दोनों की सेहत को दृष्टिगत रखते हुए एक वृहद कार्ययोजना पर समाज को जोड़ने की पहल कर रहे है। आज देश दुनिया के लोग मोटे अनाज को अच्छी सेहत का सर्वोत्तम उपाय मान रहे है। श्री मुकाती ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम अपने ही क्षेत्र में उत्पादित होने वाले मोटे अनाज को क्यों न अपनी प्राथमिकता और थाली में शामिल करें। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा हरदा जिले के वनांचल और उससे जुड़े क्षेत्रों का सर्वे कर यहां के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में जिन किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है उन्हें सूचीबद्ध कर उनके द्वारा बोई गई फसलों और उसके रकबे को भी एकत्रित किया जा रहा है। जिससे हमें इस बात का आंकलन हो सके की किस किसान के पास कितने रकबे में कौन सी फसल बोई गई है और उसका अनुमानित उत्पादन कितना होगा।

इसी तरह हम खण्डवा जिले की हरसूद तहसील, नर्मदापुरम के केसला ब्लाक तथा बैतूल जिले के शाहपुर, घोड़ाडोंगरी जैसे वनक्षेत्रों से जुड़े लगभग 500 गांवों का सर्वे कर रहे है। यहां उत्पादित होने वाले मोटे अनाज को सीधे किसानों से क्रय किया जाएगा। इसी क्षेत्र के वनवासियों और ग्रामीण महिलाओं का समूह बनाकर उस अनाज की प्रोसेसिंग की जाएगी। उन्हीं समूहों के माध्यम से तैयार किए गए अनाज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की तमाम व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हमें समाज को जागृत करते हुए मोटे अनाज की खरीदी और उससे अपनी सेहत के साथ ही इन कम जोत वाले वनक्षेत्रों के किसानों की माली हालत को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करना होगा। परिचर्चा दौरान श्री मुकाती ने कहा कि उपभोक्ता समूह को हम उत्पादन क्षेत्र और वहां की जाने वाली प्रोसेसिंग यूनिट पर भी सीधे ले जाकर उस तमाम प्रक्रिया से रुबरु करवाएंगे जो परंपरागत रुप से तैयार होते अपने उन उत्पादों को देख सके। जैसे तुअर दाल बनाने का कार्य उसी क्षेत्र की महिलाओं के समूह को दिया जाएगा। उसकी क्वालिटी जांचने का कार्य भी महिला समूह को ही सौंपा जाएगा।

श्री मुकाती द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव और सुझाव को उपस्थित जनसमूह ने सराहते हुए उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी की बात कही। शहरी क्षेत्र के लोगों ने इस बात में भी उत्साह दिखाया कि वह ऐसे प्राकृतिक उत्पादों को न केवल स्वयं खरीदेंगे बल्कि अपने से जुड़े अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। नि:संदेह श्री मुकाती के माध्यम से की जाने वाली यह एक सराहनीय पहल है। जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मानव स्वास्थ्य की दिशा में भी एक जनआंदोलन बनकर प्राकृतिक खेती और उससे उत्पन्न अनाज का उपभोग करने वाला एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो सकता है। यह कार्य आने वाले समय में समाज और सरकार दोनों के लिए दिशा प्रदान कर सकता है।

सेहत से खिलवाड़ करती सरकार की दिशाहीन नीति

हरदा। औद्योगिक क्रांति और भौतिक विकास के चक्कर में हमने प्रकृति के साथ भरपूर खिलवाड़ किया है। जिसके दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। पर्यावरण प्रदूषण और ऋतु परिवर्तन के रुप में दुनिया के समक्ष आए दिन देखने को मिल रहे है। हमारी सरकार द्वारा भी लम्बे समय तक इसकी अनदेखी किए जाने और हरित क्रांति के नाम पर जो कार्य किए गए वह दिशाहीन होकर प्रकृति के विपरीत मानव स्वास्थ्य ही नहीं अपितु जीव मात्र से खिलवाड़ करने वाले साबित हो रहे है। बेशक हरित क्रांति की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम था, लेकिन उसकी दिशाहीनता के चलते आज दुष्परिणाम देखने को मिल रहे है। शासन ने कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जिन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को अनुमति प्रदान की वही आज जल, जमीन और जीवन के लिए घातक सिद्ध हो रहे है। कैसी विडम्बना है कि आज हम उन कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहे है जिसके उत्पादन में हमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं, चावल का हमारे द्वारा निर्यात किया जा रहा है। जबकि हमारा भूजल स्तर निरंतर घटता जा रहा है। हमारे किसानों ने इसी आधुनिक कृषि तकनीक के चलते नदी-नालों तक के किनारों पर कृषि कार्य करना शुरु कर दिया। वहीं वनांचल से जुड़े क्षेत्रों में भी देखादेखी के चलते परंपरागत कृषि से हटकर आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया जाने लगा। जिसके चलते इस क्षेत्र के नदी-नाले का पानी गेहूं, चने, मूंग जैसी फसलों के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु दौरान जलसंकट उभरने से न केवल रहवासियों के लिए अपितु वन्य प्राणियों के लिए भी पीने के पानी की समस्या पैदा होने लगी। हरदा जिले के मालेगांव जैसे वनग्रामों में पानी परिवहन कर ले जाया जाने लगा। वन्य प्राणी पानी की तलाश में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आने लगे और शिकारियों के शिकार होने का सिलसिला शुरु हो गया। वहीं दूसरी ओर हमने खेती के चक्कर में वनों का सफाया करना शुरु कर दिया जिससे भूजल स्तर बनाए रखने वाले वृक्षों की कमी सीधे तौर पर देखी जाने लगी। परिणाम यह रहा कि कभी इमारती सागौन का भंडार कहलाने वाला भारत आज लगभग 80 हजार करोड़ रुपए की इमारती लकड़ी आयात करने लगा। हम जलस्त्रोत को जीवित करने वाली सागौन तो आयात कर रहे है और जल का दोहन करने वाली फसलें निर्यात करने लगे है। यह देखा जाए तो सीधे तौर पर शासन की लचर कार्यशैली और दिशाहीन कार्ययोजना का ही परिणाम है। सरकार को भौगोलिक परिस्थिति अनुसार कार्ययोजना बनाया जाना चाहिए। जिससे वहां की भूमि अनुकूल उत्पादन हासिल किया जा सके। चूंकि विषमता एक प्राकृतिक सत्य है कोई भूमि कछारी होती है तो कोई पठारी और कहीं बर्फ के पहाड़ है तो किसी जगह तपने मरुस्थल है। मनुष्य आदिकाल से ही अपनी संवेदनाओं के कारण आदान-प्रदान कौशल क्षमताएं और संसाधनों का नैतिक, व्यवहारिक और दूरदृष्टि प्राकृत्य प्रवाह अनुसार चलता रहा है। फिर चाहे वह सनातन सभ्यता हो, पाश्चात्य हो, विविध धार्मिक अनुष्ठान हो या सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक संतुलन को समाप्त करने का पक्षधर रहा है। जबकि सरकार को ऐसी परिस्थिति में कठोर कानून के तहत कार्ययोजना बनाना चाहिए। निरंतर घटते वन और वहां के गिरते भूजल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए वन्य क्षेत्रों में परंपरागत प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए, वहीं पर्यावरण और प्राणियों की सेहत को दृष्टिगत रखते हुए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसे उत्पादों को शासन स्तर पर किसी भी तरह से प्रोत्साहन राशि देने या उन्हें समर्थन मूल्य पर क्रय करने जैसी कोई योजना नहीं बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्रों की वृद्धि और इमारती लकड़ी के रोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिससे आज हम लगभग 80 हजार करोड़ की लकड़ी के निर्यात से बचकर स्वयं आत्मनिर्भर हो सके। हरदा जिले में आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर कृषक का आह्वान करते हुए बड़े पैमाने पर निजी भूमियों पर सागौन रोपण का कार्य इसी भावी योजना इंगित करता है।

पानी का उपयोग कर पैदा होने वाली फसलों का निर्यात कर रहे है और पानी बचाने वाले सागौन का आयात

सागौन का रोपण बनाएगा किसानों को समृद्ध

■ Pragyna Divakar
Bangalore

■ Tuman Baruah
Bangalore

सागौन एक उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी का पेड़ है जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। यह मध्यप्रदेश के जंगलों सहित विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियों में पनपता है। अपनी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए जाना जाने वाला सागौन अपनी ताकत, स्थायित्व और क्षय के प्रतिरोध के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। यह ऊंचाई में 30-40 मीटर तक बढ़ सकता है, जिसका जीवनकाल 100 से अधिक है। सागौन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने और विभिन्न प्रकार की मिट्टी के अनुकूल होने की क्षमता है।

कृषि वानिकी कार्बन परियोजना में भाग लेने वाले भारतीय किसानों के लिए टिकाऊ सागौन मूल्य श्रृंखला एक परिवर्तनकारी अवसर के रूप में उभरी है। सागौन में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए किसानों की आजीविका बढ़ाने की अपार क्षमता है। सागौन की दुनिया में गहराई से जाकर हम सभी भाग लेने वाले किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि और पारिस्थितिक लचीलेपन की दिशा में एक मार्ग खोजते हैं।

पर्यावरणीय लाभ

सागौन की व्यापक जड़ प्रणाली इसके सबसे लाभकारी पहलुओं में से एक है। जड़ें गहराई तक बढ़ती हैं और मिट्टी के कणों को पकड़कर रखती हैं। यह मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे यह स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। इस प्रकार, यह पेड़ विशेष रूप से नर्मदा नदी के बेसिन के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां पानी अक्सर उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है।

सागौन जलवायु परिवर्तन को कम करने और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ के रूप में यह वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और इसे अपनी लकड़ी में समाहित कर लेता है। सागौन के बागान कार्बन पृथक्करण में योगदान करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, सागौन के पेड़ छाया प्रदान करते हैं, मिट्टी संरक्षण में योगदान करते हैं, और क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। सागौन के पेड़ों द्वारा प्रदान की गई छाया अन्य फसलों के लिए अनुकूल माइक्रोक्लाइमेट बना सकती है। हालाँकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनियमित रूप से उगाया गया सागौन आक्रामक और खतरनाक हो सकता है। सागौन की जड़ें ऊपरी मिट्टी में क्षैतिज रूप से फैलती हैं और अन्य पेड़ों और पौधों को मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करने की अनुमति नहीं देती हैं। इस कारण से कृषि वानिकी परियोजना यह सुनिश्चित करती है कि सागौन को उचित घनत्व पर लगाया जाए जहां यह अन्य पौधों को परेशान न करें। रोपण चरण से ही पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, जो किसान इस परियोजना का हिस्सा हैं, उन्हें टिकाऊ तरीके से सागौन उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उन्हें और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा।

आर्थिक लाभ और सागौन मूल्य श्रृंखला

सागौन की खेती के आर्थिक लाभ किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सागौन के पेड़ों का विकास चक्र लंबा होता है लेकिन वे इस चक्र के विभिन्न चरणों में उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी प्रदान करते हैं। सागौन का मूल्य समय के साथ तेजी से बढ़ता है - जितना अधिक समय तक इसे उगाया और पोषित किया जाता है, लकड़ी का उत्पादन उतना ही बेहतर होता है। सागौन का रोपण करके किसान अपने वृक्षारोपण का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं। यह अतिरिक्त राजस्व धारा उनकी कृषि आय को पूरक कर सकती है और वित्तीय स्थिरता में योगदान कर सकती है। सागौन को उसके बहुमुखी उत्पादों की श्रृंखला के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सागौन की लकड़ी टिकाऊ, मौसम प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी होती है जो इसे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की के फ्रेम, कॉलम और बीम के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है। सागौन की लकड़ी में मौजूद ताकत और प्राकृतिक तेल इसे दीमक और

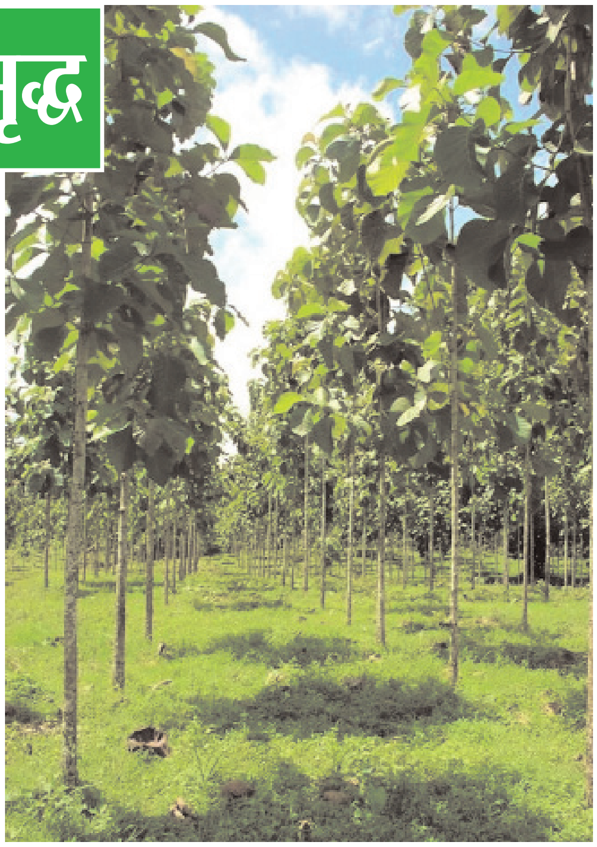

फंगल क्षय के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं।

सागौन न केवल लकड़ी के रूप में बल्कि अपने आयुर्वेदिक उपयोग के लिए भी मूल्यवान है। सागौन की पत्तियों, छाल और तेल का उपयोग उनके चिकित्सीय लाभों के लिए किया जाता है। पत्तियों में त्वचा रोगों के लिए रोगाणुरोधी गुण होते हैं, छाल पाचन में मदद करती है, और सागौन का तेल त्वचा और बालों को आराम देता है। इसके अतिरिक्त, माना जाता है कि सागौन जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट लाभ प्रदान करता है।

अपने आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के अलावा, सागौन का भारत में एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। इसका उपयोग सदियों से मंदिरों, महलों और पारंपरिक फर्नीचर के निर्माण में किया जाता रहा है। अयोध्या में आगामी राम मंदिर में भी मुख्य द्वार सहित सभी लकड़ी के काम में सागौन का उपयोग किया जाएगा। सागौन की खेती करके, किसान इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और जारी रखने में योगदान देते हैं।

भोजन में पोषक तत्वों की कमी दूर करेगा मोटा अनाज

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशियन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अनाज, दालों, फलों एवं सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स आदि की मात्रा में 6 से लेकर 20 प्रतिशत तक की कमी आई है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी के चलते न केवल हमारी शारीरिक क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ा है बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती जा रही है। यह विचार डॉ. विनोद यादव द्वारा व्यक्त करते हुए कहा गया कि वर्तमान खानपान का सीधा असर हमारे बच्चों की सेहत पर स्पष्ट देखा जाता है। हम स्वाद के चक्कर में पोषण की लगातार अनदेखी कर रहे है। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन संतुलित व पोषक हो यह जरुरी नहीं है। यदि आप घर का खाना नहीं खा रहे है तो यह अधिक संभावना है कि आपके भोजन में वसा, चीनी, नमक और कार्बोहाइड्रेड की मात्रा अधिक हो, लेकिन मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा कम हो। जबकि हमारे दैनिक आहार में यह सभी तत्व संतुलित मात्रा में होना चाहिए। आज हमने प्रोस्टेड फूड, फास्ट फूड और डिब्बा बंद फूड को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। जबकि यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे है। आयुर्वेद के मतानुसार व्यक्ति को भोजन अपनी प्रकृति, आयु और ऋतु के अनुसार करना चाहिए ताकि खाया हुआ भोजन सेहत के लिए फायदेमंद हो। अगर वास्तव में हम अपनी सेहत के प्रति सजग है तो हमें मोटे अनाज को अपनी थाली में जगह देना होगा। मोटा अनाज पोषक

तत्वों का खजाना है। डॉ. विनोद यादव के अनुसार वर्तमान में अधिकांश खाद्य सामग्रियां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से प्रभावित होने के कारण हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रुप से उत्पादित किए जाने वाले अनाज को हमें महत्वता देना होगा। उन्होंने कहा कि बीमारी की स्थिति में जहां हम पैसा खर्च करने के बाद भी शारीरिक और मानसिक रुप से परेशानी झेलते है वहीं अगर हम प्राकृतिक उत्पादों को जैविक उत्पाद की तुलना महंगे दाम पर भी खरीदकर उसका उपयोग करें तो भी वह हमारे लिए लाभकारी है। हमें अपने दैनिक आहार में गेहूं के साथ ही अन्य अनाजों को मिक्स करना चाहिए ताकि भोजन अधिक पौष्टिक व सुपाच्य हो। चना, जौ, जई, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, कोदा-कुटकी जैसे अनाज गेहूं के साथ मिक्स कर पिसाया जाना चाहिए। आज भी हमारे देश के वनांचलों में ऐसी प्राकृतिक संपदाएं विद्यमान है जो हमें स्वस्थ्य और तंदुरस्त रख सकती है। अगर हम समीक्षा करें तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना वनांचलों में रहने वाले लोगों के सेहत और शारीरिक क्षमता अधिक अच्छी होती है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी तुलना में कई गुना अधिक होती है। चूंकि इस क्षेत्र के लोग शुद्ध वायु के साथ ही शुद्ध पौष्टिक अनाज का उपयोग करते है। ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर जैसे अनाज इनके दैनिक भोजन में शामिल होते है। हमें अपने भोजन में इन सामग्रियों को शामिल करना ही होगा वरना हम आने वाले समय में ऐसी बीमारियों की चपेट में आएंगे जो हमारी पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगी। चूंकि वर्तमान कृषि पद्धति के माध्यम से जो कृषि उत्पाद प्राप्त किए जा रहे है वह सेहत के लिए बेहद हानिकारक है।

भारतीय संस्कृति में जल पूजनीय है। पवित्र नदियों के जल को हम माता के रूप में पूजते हैं। धरती का उद्गम जल के गर्भ से हुआ है। मनुष्य के जन्म से ही उसका रिश्ता पानी से हो जाता है, जो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। मनुष्य का परिचय नदियों के तटीय स्थानों से होता रहा है। प्राचीनकाल से ही मानवीय बसाहट ही नदियों के किनारे स्थापित हुई। आज भी गांवों और नगरों का विकास पानी की उपलब्धता को देखते हुए किया जाता है। कृषि विकास हो या औद्योगिक विकास, इसका आधार पानी ही है। मनुष्य सहित सभी जीव प्राणियों के जीवन का आधार जल ही है।

पानी बचाना हमारी संस्कृति

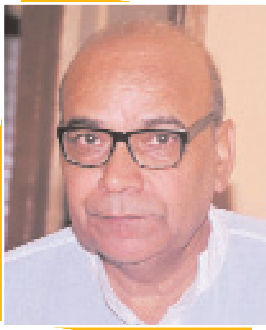

■ श्रीराम माहेश्वरी
(लेखक पर्यावरणविद् एवं वरिष्ठ साहित्यकार है।)
मो 9926372750

बचपन से हमारे संस्कारों में जल का प्रयोग शुरू हो जाता है। पूजन शुरू करते हैं तो देवी देवताओं को जल अर्पित करते हैं। पाठ शुरू करने पर जल का आचमन करते हैं। कलश यात्रा हो या पूजा में रखे जाने वाले जल कलश की बात हो, हर समय जल की पूजा हमारे संस्कारों में रची बसी है। सुबह उठते ही हम नित्य क्रिया करते हैं। स्नान करते हैं, भोजन बनाते हैं। पौधों और खेतों को पानी देते हैं। पशु पक्षियों को जल देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दिनचर्या की शुरुआत जल से होती है और रात को सोने तक हम जल का उपयोग करते रहते हैं। स्पष्ट है कि जल के बिना जीवन असंभव है। यह जानते हुए भी हम दैनिक व्यवहार में पानी का अपव्यय करते हैं। जल को प्रदूषित करते हैं। जलापूर्ति की पाइप लाइनों में लीकेज कई महीनों तक चलते रहते हैं। इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमें जल संरक्षण और जल की बचत की आदत अपनाने की जरूरत है। तभी हम अगली पीढ़ियों को जल उपयोग के लिए दे सकेंगे।

स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक बड़े और छोटे बांध बनाए गए। जल संरक्षण की योजनाएं लागू की गई, परंतु आज भी हम देखते हैं कि ग्रीष्मकाल आते ही जलसंकट शुरू हो जाता है। देश के अनेक राज्यों में जलसंकट के कारण त्राहिमाम मची रहती है। शुद्ध जल लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। खेतों की प्यास बुझ नहीं पा रही है। प्यास से आम आदमी भी परेशान है। जहां जलस्त्रोत हैं वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। हमने औद्योगिक विकास की जो राह चुनी उसकी शुरुआत से ही हमने प्रदूषण का ध्यान नहीं रखा, इसलिए यह दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि है कि दुनिया के 2.1 अरब लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। पानी प्राप्त करने के लिए करोड़ों की आबादी ऐसी है, जिसे साफ पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भूगर्भ के जल में आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे प्रदूषक तत्व बढ़ रहे है, इससे पानी प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषित पानी का उपयोग करने से अनेक बीमारियां हो रही हैं। इस देश में नदियों को सदानीरा कहा जाता था, परंतु आज स्थिति उलट है। आज नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। नदियां सूख रही हैं, उनमें प्रदूषण बढ़ने से वे गंदे नाले में तब्दील हो रही हैं। पानी बचाने की आज हमें पानी बचाने के लिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जल संकट की समस्या के कारण कई स्थानों पर लोगों को पानी के भीतर खड़े होकर पानी बचाने के आंदोलन को करना पड़ता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे देश में इतना जल उपलब्ध है, फिर भी जल संकट क्यों बढ़ रहा है। प्राचीन ग्रंथों में जल सूक्त जल महत्व का अद्भुत उदाहरण है। पूर्वजों का कहना है कि हम पानी का मान रखेंगे, तो पानी हमारा मान रखेगा। इस बात को हमें समझना होगा।

ऋषि-मुनियों और पूर्वजों ने जल, अग्नि, आकाश और वायु को देवता माना और हमारे कर्मों के साथ पाप पुण्य से उन्हें जोड़ दिया। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। यह हमें बताया। भूखे को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, यह हमारे संस्कारों में है। हमारे यहां गर्मियों में प्याऊ खोलकर पानी पिलाने की परंपरा रही है। शहरों में अब धीरे-धीरे यह परंपरा खत्म हो रही है। पानी अब बिकने लगा है। यह सत्य है कि पानी प्रकृति प्रदत्त है। इसे नैतिक रूप से बेचा नहीं जा सकता। इसके बावजूद निजी व्यापारी और कंपनियां बोतलबंद पानी का व्यापार कर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। नगरीय निकाय और पंचायत भी पानी की आपूर्ति करके मोटा शुल्क वसूल कर रही हैं। इस शुल्क में रखरखाव के नाम पर साल दो साल में वृद्धि कर रही हैं। जनता पर इसका बोझ भी पड़ रहा है, फिर भी जिम्मेदार मौन हैं। अन्न, पानी, बिजली, कपड़ा ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर शुल्क न बढ़ाया जाए। स्टेशन, बस स्टैंड और बस्तियों में निशुल्क पानी जनता को मुहैया कराया जाए। जगह-जगह नगरीय निकायों द्वारा प्याऊ लगवाकर प्यासे लोगों को पानी पिलाया जाए। शुल्क वसूल करके यदि जल दिया जा रहा है तो यह व्यापार है, धर्म नहीं। अन्न जल से प्रजा का पोषण करना राज दायित्व है। यही हमारी संस्कृति है।

सरकार और नगरीय निकायों को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही पानी की बचत करना जनता और उपभोक्ताओं का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जल की बूंद बूंद का महत्व समझाने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है।

जैविक उर्वरकः टिकाऊ खेती के लिए गेम-चेंजर

खेती की जटिल दुनिया में उर्वरकों का महत्वपूर्ण विकल्प न केवल फसल की प्रचुरता बल्कि नियोजित प्रथाओं की स्थिरता को भी निर्धारित करता है। विकल्पों के इस स्पेक्ट्रम के भीतर, जैविक उर्वरकों के उदय ने एक परिवर्तनकारी बदलाव को प्रज्वलित किया है, जो फसलों, मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। अपने सिंथेटिक समकक्षों के विपरीत, जैविक उर्वरक फसलों को पोषण देने और भूमि को समृद्ध करने के लिए एक सर्वव्यापी, पर्यावरण अनुकूल रणनीति पेश करते हैं।

अच्छी खेती और अच्छा स्वास्थ्य

खाद, पशु खाद और फसल अवशेषों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जैविक उर्वरक निस्संदेह महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदान करते हैं, जो मजबूत फसल विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे जैविक उर्वरक बेहतर एकत्रीकरण को बढ़ावा देकर मिट्टी की संरचना को बढ़ाते हैं। यह संरचनात्मक सुधार जल घुसपैठ और प्रतिधारण को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है और नमी का स्तर बेहतर बनाए रखा जाता है, जिससे अत्यधिक सिंचाई पर निर्भरता कम हो जाती है। जाहिर तौर पर दूसरी ओर सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि किसी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दरअसल, 2012 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 40 प्रतिशत से अधिक इंडोनेशियाई सब्जी किसानों ने अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किए गए क्लिनिकल परीक्षण के अनुसार लगभग 22 प्रतिशत किसानों में किडनी या लीवर की कार्यप्रणाली में गिरावट के लक्षण दिखाई दिए। ऐसे उदाहरणों से संकेत मिलता है कि किसानों का कल्याण कृषि उत्पादन में उनके योगदान के समान ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर जैविक उर्वरकों का उपयोग अंतर को पाट सकता है क्योंकि यह अपने प्राकृतिक मूल के कारण स्वाभाविक रूप से कम खतरे प्रस्तुत करता है। इसके साथ जैविक उर्वरक कृषक समुदायों की रीढ़ बनने वाले परिवारों के लिए सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने में एक दुर्जेय सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं।

■ Chubasenla Jamir
Bangalore

■ Tuman Baruah
Bangalore

बेहतर कल के लिए हरित दृष्टिकोण

जैविक उर्वरकों के पारिस्थितिक लाभ उन खेतों से कहीं अधिक हैं, जिनका वे पोषण करते हैं। जबकि सिंथेटिक उर्वरक पोषक तत्वों के अपवाह और जल प्रदूषण में योगदान करते हैं, उनके जैविक समकक्ष पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करते हैं। उपज क्षमता बढ़ाने के अलावा, जैविक उर्वरक मिट्टी की जैव रासायनिक गतिविधि और भौतिक संरचना में भी सुधार कर सकते हैं - एक प्रभाव जो मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन के कारण प्रकृति में उल्लेखनीय रूप से दीर्घकालिक होता है। इसलिए आज की कृषि कथा में जैविक उर्वरकों के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। क्रमिक और संतुलित पोषण प्रदाताओं के रूप में अपनी भूमिका से परे वे मिट्टी के लचीलेपन, जैव विविधता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के दृढ़ समर्थकों के रूप में खड़े हैं। जैसे-जैसे किसान ग्रह की सुरक्षा करते हुए बढ़ती आबादी को खिलाने में सबसे आगे रहते हैं, जैविक उर्वरकों को अपनाना पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के माध्यम से समृद्धि पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरता है।

प्रकृति का अमूल्य उपहार वन मानव के लिए भी बहुत उपयोगी है अतः मनुष्य का दायित्व है कि वह हमेशा वन संस्कृति की वन संपदा का संरक्षण संवर्धन करता रहे। मानव जीवन में वन ऑक्सीजन के साथ-साथ शुद्ध वायु प्रदान करते हुए ना केवल यह प्रदूषण और बाढ़ को रोकते हैं अपितु उत्पादन के क्षेत्र में कच्चा माल जैसे कपास, कत्था, रेशम, दियासलाई, चटाई गोंद, शहद, कागज, बीड़ी बनाने के लिए तेंदूपत्ता, पत्तल, रबर, लाख, खिलौने दियासलाई आदि भी उपलब्ध कराते है। इनसे कुटीर अथवा लघु उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलता है।

प्रकृति में वन संपदा का महत्व

■ श्रीमती सुनीता शर्मा सिद्धि
(लेखिका वरिष्ठ साहित्यकार है)

भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि-मुनियों ने बहुत पहले से ही वन संपदा का अवलोकन कर लिया था इसीलिए प्राचीन धर्म ग्रंथों में वनों को देवता का स्थान दिया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में पीपल, बरगद, अशोक, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों का देवतुल्य मानकर उनकी पूजा-अर्चना के महत्व को स्वीकारा है। अतः इसी परिपेक्ष में हम भारतीय संस्कृति को वन उपवन की संस्कृति भी कह सकते हैं। इस धरती पर वन संपदा हर जीव जंतु के लिए आवश्यक है।

यदि वन समृद्ध है तो ये मनुष्य के साथ-साथ पशु पक्षियों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि पशु पक्षी तो पूरी तरह से वन संपदा पर ही निर्भर हैं। वनों में काफी मात्रा में तरह-तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अतः ये मूक पशु, पक्षी, कीट और स्तनधारी जीव वनों से प्राप्त इन्हीं वनस्पतियों के अंतर्गत फल, फूल, घास, फूस, पत्ते आदि चारा खाकर अपनी क्षुधा मिटाते हुए मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन की व्यवस्था स्वंय कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बरगद, पीपल, आम, नीम, अशोक, देवदार आदि छायादार घने वृक्ष भी सदैव इन पशु पक्षियों का आश्रय स्थल रहे हैं। हर रुप, रंग, कद, काठी के अनेकों पशु, पक्षी वनों के सौंदर्य को बढ़ाते हुए मुक्त विचरण करते रहते हैं।

पशु पक्षी स्वच्छंद घूमते
वन उपवन की शोभा बनते
पेड़ पौधों से भूख मिटा कर
सदा इन की छाया में रहते
ईश्वर प्रदत्त इस पृथ्वी पर

प्रकृति का अमूल्य उपहार वन मानव के लिए भी बहुत उपयोगी है अतः मनुष्य का दायित्व है कि वह हमेशा वन संस्कृति की वन संपदा का संरक्षण संवर्धन करता रहे। मानव जीवन में वन ऑक्सीजन के साथ-साथ शुद्ध वायु प्रदान करते हुए ना केवल यह प्रदूषण और बाढ़ को रोकते हैं अपितु उत्पादन के क्षेत्र में कच्चा माल जैसे कपास, कत्था, रेशम, दियासलाई, चटाई गोंद, शहद, कागज, बीड़ी बनाने के लिए तेंदूपत्ता, पत्तल, रबर, लाख, खिलौने दियासलाई आदि भी उपलब्ध कराते है। इनसे कुटीर अथवा लघु उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलता है। वर्तमान में मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ में ग्रामीण अंचल के बहुत से लोग आज भी इसी वन सम्पदा के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। फर्नीचर और इमारती लकड़ी के लिए तो मनुष्य पूरी तरह से वनों में स्थित विशाल पेड़ों जैसे शीशम, सागौन, देवदार, चीड़ आदि की लकड़ियों पर ही निर्भर है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां दालचीनी, हरड़, बहेड़ा, रीठा, अर्जुन की छाल, चंदन की लकड़ी और अन्य अति उपयोगी वनोंषधियां मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके व्यापारिक क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी होती हैं।

हरियाली से हर्षित वन
पशु पक्षियों को लुभाते हैं
मानव भी प्रफुल्लित होकर
वन संपदा से लाभ उठाते हैं

वन जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त तापमान को नियंत्रित करके न केवल मिट्टी के बहाव को रोक कर वर्षा को आकर्षित करते हैं। अपितु वह भूमिगत जल की व्यवस्था करने में भी सहायक हैं। विश्व के अधिकांश देशों में वनवासी समाज के लोगों का जीवन तो पूरी तरह से वनों पर ही निर्भर है। वनों से मांस, खाल, ऊन, ईंधन, फल, फूल और अनेक वनोंषधियां प्राप्त करते वनवासी अपनी दिनचर्या आज भी इन वन उपवन या जंगलों में ही गुजारते रहे हैं।

वन मानव समाज को अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भी अभिभूत करते है। यहां पर भ्रमण करते मनुष्य वन उपवन के रमणीय स्थानों को देखते हुए अति प्रसन्नता का अनुभव करते है। इसके अलावा मनुष्य को यहां पर आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। भगवान बुद्ध को तो वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः इसी के अंतर्गत ऋग्वेद में भी वनदेवी की उपासना की बात कही गई है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करने के लिए वनों की ओर प्रस्थान करके ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करते थे।

यदि मानव सांसारिक जीवन में तनाव से मुक्ति चाहते है तो हरे भरे वृक्षों से युक्त वनों के बीच बैठकर वो अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते है। इसके अलावा यहां पर अनेक बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, श्वांस रोग मानसिक रोग आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति में वनों की उपयोगिता को देखते हुए ही उन्हें सुंदर नामों से संबोधित किया है जैसे मधुबन, कानन वन, सुंदरवन निधिवन आदि। वास्तव में वन हमारे पर्यावरण के मजबूत स्तंभ है। अतः इस पृथ्वी पर वन संपदा की सुरक्षा करना मानव समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।

'प्रदूषण की काली छाया से
वनों को बचाना है
निर्मल पावन प्रकृति को
कभी नहीं सताना है।'

डॉ. जोशी के प्रकृति प्रेम के कायल हो गए अमिताभ बच्चन

पद्मभूषण पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की देश-दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण को लेकर यह चिंता टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने उभरी तो वह भी डॉ. जोशी के कायल हो गए।

हवा, मिट्टी, जंगल पानी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में यह और भी बड़ी चुनौती होने जा रही है। दुनिया में आधे से ज्यादा वन खत्म हो चुके हैं। देश की ज्यादातर नदियां मरना शुरू हो गई हैं। हवा, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, वही प्राण लेना चाहती है। पद्मभूषण पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की देश-दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण को लेकर यह चिंता टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने उभरी तो वह भी डॉ. जोशी के कायल हो गए। श्री बच्चन ने इस कर्मवीर के साथ खुद को जोड़ते हुए कहा कि अब हमारे चिंतित होने का समय आ गया है। यदि अब भी न संभले तो न संभलने का मौका मिलेगा और न संभालने का। यही नहीं हॉट सीट पर डॉ.जोशी का साथ देने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग बसु भी उनसे खासे प्रभावित हुए। श्री बसु बोले कि पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर हम गंभीर होंगे और डॉ. जोशी के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।

पद्मभूषण डॉ.जोशी हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन (हेस्को) के माध्यम से देश भर में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे हैं तो आत्मनिर्भरता को लोक विज्ञान व विज्ञान का समावेश कर गांवों की बेहतरी के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार निवासी डॉ.जोशी न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तर्ज पर सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) पर निरंतर जोर दे रहे हैं, बल्कि हिमालयी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर संवारने की कोशिशों में जुटे हैं।

इस सबको देखते हुए कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें कर्मवीर स्पेशल शो में आमंत्रित किया। इसमें डॉ.जोशी शुक्रवार को फिल्म निर्देशक अनुराग बसु के साथ हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। वह न सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देंगे, बल्कि देश-दुनिया के पर्यावरण समेत तमाम मसलों पर अपनी बात रखेंगे। वह इस शो में हिमालयी क्षेत्र से शामिल होने वाले ऐसे पहले कर्मवीर है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। डॉ.जोशी ने कहा कि शो के दौरान पर्यावरण, आत्मनिर्भरता, जीईपी जैसे विषयों पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर हालात गंभीर हो रहे हैं। यदि आज नहीं चेते तो आने वाले दिनों में दुश्वारियां अधिक बढ़ जाएंगी। अमिताभ बच्चन ने भी इसे स्वीकारा। डॉ.जोशी के अनुसार शो के दौरान जीईपी के अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर उनके साथ काम करने की इच्छा जताई है।

हर वक्त हिमालय की चिंता

पिछले 37 वर्षों से डॉ.जोशी पारिस्थितिकी और आर्थिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन मन में चिंता हर वक्त हिमालय और पर्यावरण की रहती है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में प्राध्यापक रहे डॉ.जोशी ने 1983 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिर हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन (हेस्को) के जरिये अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। इसके बाद तो पर्यावरण, गांव व समाज की सेवा में जुट गए। 'लोकल नीड मीट लोकली' के सूत्रवाक्य पर चलते हुए स्थानीय जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया और पर्यावरण को बचाने की मुहिम भी छेड़ी। हिमालय और हिमालयवासियों के हितों की चिंता के मद्देनजर नौ सितंबर को हिमालय दिवस के आयोजन की नींव पड़ने के पीछे भी डॉ.जोशी की सोच थी।

25 लाख की रकम जीती

कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में पर्यावरणविद् डॉ.जोशी और फिल्म निर्देशक बसु की जोड़ी ने हॉट सीट से सदी के महानायक के सवालों का बखूबी जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक इस जोड़ी ने 25 लाख की रकम जीतने में कामयाबी पाई।

वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट बाजार 2030 तक 250 अरब डॉलर का होगा : विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) कार्बन क्रेडिट के वैश्विक बाजार में तेजी का रुझान रहने और 2030 तक 250 अरब डॉलर के स्तर को छूने की उम्मीद है। उद्योग से जुड़े के एक कार्यकारी ने यह जानकारी दी। ईकेआई एनर्जी सर्विसेज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनीष डबकरा ने साक्षात्कार में कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और मांग में कमी सहित कई कारणों से कार्बन क्रेडिट बाजार को झटका लगा, जिससे कीमतें 80 प्रतिशत तक गिर गई। डबकरा ने कहा कि स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट से जुड़ा बाजार जिसका मूल्य 2021 में करीब दो अरब डॉलर था, उसमें मंदी देखी गई और अब यह 50 करोड़ डॉलर पर आ गया है। हालांकि, विभिन्न रेटिंग और शोध कंपनियां कार्बन बाजार में सुधार पर जोर दे रही हैं। बार्कलेज की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों की कड़ी जलवायु नीतियों, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत उनकी प्रतिबद्धताओं तथा कॉरपोरेट स्थिरता लक्ष्यों जैसे कारकों से कार्बन क्रेडिट बाजार में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके 2030 तक 250 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने पहले कहा था कि सरकार भारत को कार्बन क्रेडिट का बाजार बनाने के लिए कदम उठा रही हैं। इससे देश के एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश स्थित ईकेआई एनर्जी सर्विसेज दुनिया भर में एक अग्रणी कार्बन क्रेडिट डेवलपर और आपूर्तिकर्ता है। कार्बन क्रेडिट को कार्बन ऑफसेट भी कहा जाता है। यह एक बाजार-आधारित प्रणाली है, जिसे ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है।

कहा कि विभिन्न देशों की कड़ी जलवायु नीति

कहा कि विभिन्न देशों की कड़ी जलवायु नीति

नई दिल्ली। भारत जापान के साथ कार्बन क्रेडिट निर्यात के लिए एक रूपरेखा पर काम कर रहा है और इस सुविधा को अन्य देशों तक विस्तारित करने पर विचार कर रहा है जो उससे हरित हाइड्रोजन (जीएच2) खरीदते हैं, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा ।

हम भारत के बाहर कार्बन क्रेडिट बेचने पर काम कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे लिए हरित हाइड्रोजन खरीद रहे हैं। जापान ने हमें कार्बन व्यापार पर एक मसौदा भेजा है। और हम इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम संभवतः इसके साथ आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा। सरकार ने घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजार को समर्थन देने के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए 8 अगस्त, 2022 को कार्बन क्रेडिट नीति को संशोधित किया था। श्री सिंह ने कहा कि सरकार सौर और पवन परियोजनाओं जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के लिए विदेशी व्यापार विकल्प तलाशने के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि अन्य नवीकरणीय क्षेत्रों में जो कार्बन क्रेडिट भी उत्पन्न करते हैं, हम बाद के चरण में इसी तरह के व्यापारिक विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के चालकों में से एक है, जो सबसे कम लागत पर उत्सर्जन में कटौती की पेशकश करता है। अनुमान है कि भारत कार्बन क्रेडिट निर्यात की अनुमति देकर अगले 50 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले 35 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान को रोक सकता है। कार्बन क्रेडिट निर्यात की अनुमति दी जा सकती है, जापान के साथ रूपरेखा तैयार की जा रही है।

तपती धरती संपादक मण्डल | सलाहकार संपादक गौरीशंकर मुकाती | संपादक प्रहलाद शर्मा | प्रबंध संपादक श्रीराम माहेश्वरी, भोपाल | अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि संदीप राय चौधरी, सिंगापुर | राष्ट्रीय प्रतिनिधि विक्रांत तिवारी, मुम्बई